राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा

अपील

सम्माननीय शिक्षक बन्धु एवं बहिनों,

सादर वन्दे !

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा धनतेरस को राज्य के कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान देने की घोषणा यह कहते हुए की थी कि दीपावली पर कर्मचारियों के घर लक्ष्मी जी आ गई है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी यही जानकारी मिल रही थी कि सरकार ने 01 जनवरी 2016 से सातवाँ वेतनमान दिया है जिसका नगद लाभ अक्टूबर 2017 से मिलेगा। इस घोषणा की अधिसूचना में हुये विलम्ब से हम सभी आशंकित हो गये थे कि कर्मचारियों के हितो पर कुठाराघात होने की संभावना है।

लम्बे इन्तजार के बाद जारी अधिसूचना से हमारी आशंका यथार्थ में बदल गई। जारी अधिसूचना में वेतन स्थिरीकरण के लिये 01 अक्टूबर 2017 के मूल वेतन को ही आधार माना गया है। इस तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी/शिक्षकों का वेतन स्थिरीकरण पेंशन नियमों में किये गये संशोधन के अन्तर्गत किया जाना है। इससे सरकार की मंशा कही भी सातवें वेतनमान को 01 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को देने की नहीं लगती है। इस प्रकार पूर्व में की गई घोषणा हम सभी के लिये छलावा ही सिद्ध हुई है।

साथियों! आप सभी को विदित है कि सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते के अन्तर्गत राज्य के शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप ही वेतनमान एवं अन्य परिलाभ केन्द्र द्वारा देय तिथि से ही दिये जाने चाहिये। आज के संदर्भ में पूर्व में शिक्षक संवर्ग के वेतनमानों का तुलनात्मक अध्ययन समीचीन होगा।

		चतुर्थ वेतनमान		पंचम वेतनमान		षष्ठम् वेतनमान		
क्र.सं	पद	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र ग्रेड–पे	राज्य 01.09.2006	राज्य wef 01.07.2013
1	अध्यापक समकक्ष	1200–2050	1200–2050	4500–7000	4500–7000	4200	2800	3600
2	व.अध्यापक समकक्ष	1400–2600	1400–2600	5500–9000	5500–9000	4600	3600	4200
3	व्याख्याता समकक्ष	2000–3500	2000–3500	6500–10500	6500–10500	4800	4200	4800
4	प्रधानाध्यापक (मा.वि.)	2000–3500	2000–3500	7500–12000	7500–12000	5400	5400 P.B.-2	5400 P.B.-3
5	प्रधानाचार्य	2200–4000	2200–4000	9000–14400	9000–14400	7600	6000	6600

उक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि चतुर्थ वेतनमान में केन्द्र एवं राज्य के वेतनमान एक समान रहे थे। पंचम वेतनमान के समय राज्य में शिक्षक संवर्ग को 4000 एवं 5000 का वेतनमान दिया गया तो हमने लम्बे संघर्ष के पश्चात् 4500 तथा 5500 का वेतनमान स्वीकृत कराकर केन्द्र के अनुरूप वेतनमान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। **यह शिक्षक समाज की एकजुटता के फलस्वरूप सम्भव हो पाया था।**

लेकिन छठें वेतन आयोग के वेतनमान में फिर सरकार ने जान–बूझकर विसंगति रखते हुए शिक्षकों के वेतनमान (ग्रेड–पे) केन्द्र से कम कर दिये। संगठन इन विसंगतियों का निरन्तर विरोध कर दूर करने की माँग करता रहा है। आप को याद होगा सन् 2008 में संगठन ने जयपुर में विशाल रैली आयोजित कर सरकार के समक्ष अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया था जिसके परिणामस्वरूप कृष्णा भटनागर समिति का गठन हुआ तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने–अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन विसंगतियों को दूर करने का वायदा किया। गत सरकार ने इन विसंगतियों को आंशिक रूप से 01 जुलाई 2013 से दूर करने का प्रयास किया लेकिन केन्द्र के अनुरूप वेतनमान फिर भी प्राप्त नहीं हो सके। दिसम्बर 2013 से वर्तमान सरकार को भी संगठन ने चुनावी वायदों की याद दिलाते हुए शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का समय–समय पर आग्रह किया परन्तु विसंगतियाँ दूर करने के बजाय गत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2013 को दिये गये संशोधित ग्रेड–पे के लाभों को भी अनुसूची–V में संशोधन के तहत कर्मचारियों से छीन लिया तथा सातवें वेतन आयोग में

उनका वेतन निर्धारण निम्न स्थिति (Stage) में कर नई विसंगतियाँ उत्पन्न कर दी है। **कर्मचारियों का देशभर में कहीं पर भी इस प्रकार दिये हुए लाभ को वापस लेने की मिसाल नहीं मिलती हैं।**

बन्धुओ! संगठन ने अनेकों बार धरना/प्रदर्शन/ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से आग्रह किया था कि छठें वेतनमान में शिक्षकों की शेष रही वेतन विसंगतियों को दूर करने के बाद ही केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ देकर शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित किया जाना राज्य कर्मचारियों के हित में रहेगा। इससे सरकार और कर्मचारियों के मध्य सौहार्द उत्पन्न होगा तथा शिक्षक व कर्मचारी सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर राजस्थान के विकास के लिये कार्य करते रहेंगे। मगर राज्य की नौकरशाही में कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये किसी भी प्रयत्न को दिग्भ्रमित कर देते है। इसी कारण सरकार ने शिक्षक समुदाय के अनुरोध को ठुकराते हुए ना तो विसंगति दूर की और ना ही सातवें वेतनमान में शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप वेतनमान ही दिया। अपितु जिस सामन्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उक्त विसंगतियों को यथावत् रखते हुए दी है, उसी को पुनः इन विसंगतियों पर विचार करने के लिये 6 माह का समय देकर जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है।

साथियों! सरकार की मंशा स्पष्ट लगती है कि वह किसी भी प्रकार केन्द्र के समान वेतन/भत्ते देने के पूर्व समझौतें से हटना चाहती है जिससे भविष्य में भी केन्द्र के अनुरूप मंहगाई भत्ते, मकान किराया व अन्य भत्तें केन्द्र के अनुरूप देने की कर्मचारियों की आवाज को हमेशा के लिये बन्द कर सकें।

इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अब संघर्ष के सिवा और कोई मार्ग शेष नहीं रहा है। राजस्थान का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब–जब शिक्षक समाज ने अंगड़ाई लेकर हुंकार भरी है तब–तब सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। साथियों अब कमर कस कर संघर्ष के लिये तैयार होने का समय आ गया है। संगठन ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। इसकी पहली कड़ी में 10 नवम्बर 2017 को प्रत्येक उपशाखा मुख्यालय पर जारी अधिसूचना और सामंत कमेटी के आदेशों की होली जलाते हुए धरना–प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया है। इसके पश्चात् नवम्बर माह में ही क्षेत्रीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर शिक्षकों के साथ किये गये अन्याय की जानकारी देकर न्याय दिलवाने का आग्रह किया जायेगा। दिनांक 06 दिसंबर 2017 को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना–प्रदर्शन कर सरकार को कर्मचारियों की जायज माँगें मानने का आग्रह किया जाएगा। इसके बाद संगठन परिस्थितियों के अनुसार अपने आंदोलन को व्यापक करने के संबंध में आगामी निर्णय लेगा जिससे आप सभी को समय–समय पर अवगत कराने की व्यवस्था रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम सहित संगठन द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले अन्य आह्वानों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का कष्ट करें। आज प्रश्न केवल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तिथि अथवा एरियर का नहीं है बल्कि शिक्षक/कर्मचारी अस्मिता का है। आज लागू करने की तिथि में बदलाव हुआ है, कल महंगाई भत्ता देने में भी सरकारें अपनी सहूलियत के अनुसार समय तय करने लगेगी। किसी भी प्रकार से एक बार किसी भी विचलन को यदि हमने स्वीकार कर लिया तो फिर सरकार निरंकुश होकर कर्मचारियों का दमन करने से नहीं चूकेगी। यदि हम आज इस संघर्ष को अपना भरपूर योगदान देकर सफल नहीं बनाएंगे तो आने वाला समय और पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी।

अतः निवेदन है कि आप स्वयं तथा अपने सभी साथियों को इस यज्ञ में अपनी आहुति के लिए अपना अधिकतम देने के लिए प्रेरित करें। आप का आज का यह योगदान हमारे कल के लिए सुरक्षित भविष्य का निवेश है। सरकार ने जिस चतुराई से अब तक राज्य कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से अलग–अलग विभाजित कर रखा हैं वह भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य शिक्षकों एवं राज्य कर्मचारियों को राहत प्रदान करना होना चाहिए। असमंजस नहीं निश्चय करके संघर्ष करने का समय है। आशा है आप सभी इस संघर्ष में सक्रियता से भाग लेंगे और हमें हमारी वांछित सफलता प्राप्त होगी।

जय भारत। जय संगठन।

भवदीय

प्रहलाद शर्मा	उमरावलाल वर्मा	महावीर प्रसाद सिंहल	देवलाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
अरविन्द व्यास	अशोक कुमार शर्मा	डॉ. अरूणा शर्मा	रवि आचार्य
व.उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महिला मंत्री	प्रदेश मंत्री

उपाध्यक्ष :– देवकीनन्दन सुमन, ओमप्रकाश शर्मा, जगदीश चौधरी, नवीन कुमार, संजय शर्मा, सम्पत सिंह, शिवदत्त आर्य, राजकमल लौहार, महेन्द्र कुमार लखारा, मोहनसिंह भाटी, राजेश कुमार, दिनेश स्वर्णकार, जयमाला पानेरी